E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

भारत में गठबंधन राजनीति की प्रासंगिकता

विवेक साहू

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, (मध्य प्रदेश)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14229027

सारांश-

भारत में गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति का प्रमुख अध्याय है । प्रस्तुत शोध पत्र भारत में गठबंधन की राजनीति की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने के लिए लिखा गया है ।1989 के बाद से 2014 के काल तक भारत में विभिन्न गठबंधन सरकारें गठित हुईं। कई सरकारें अपने कार्यकाल को पूर्ण नहीं कर पाई और समय से पहले ही अस्थिर हो गई। देश को अस्थिरता के दौर से गुजरना पड़ा। गठबंधन की राजनीति ने सकारात्मक भूमिका 1999 के एनडीए सरकार के गठन के साथ ही निभाना शुरू की। इसके बाद 2004 में गठित यूपीए -1 एवं 2009 में गठित यूपीए - 2 ने भी यह सिद्ध किया कि गठबंधन सरकारें भी स्थिर सरकारें हो सकती हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 1984 के बाद पहली बार किसी एक दल को बहुमत प्राप्त हुआ लेकिन सरकार का गठन भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर एनडीए के रूप में किया। यही स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में भी रही लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से दूर रह गई एवं पुनः देश को गठबंधन की राजनीति की ओर अग्रसर होना पड़ा।

1.प्रस्तावना-

भारत विश्व का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है। भारत में विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं यह बहुमत प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं। भारत में संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता होती है सदन में जिस भी दल या गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है वह दल या गठबंधन सरकार का निर्माण करता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है जिसमें विभिन्न दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं बहुमत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रारंभ में भारत में 1952 से लेकर 1967 तक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का एक क्षत्रिय शासन कायम रहा एवं कांग्रेस पार्टी को अकेले बहुमत

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

प्राप्त होता रहा किंतु कालांतर में कांग्रेस की एक प्रभुत्वीय की व्यवस्था समाप्त होने लगी और किसी भी एक दल को बहुमत मिलना कठिन होता गया। क्षेत्रीय दलों के उभार ने भी राष्ट्रीय दलों के सम्मुख चुनौती उत्पन्न की ।1967 के चुनाव में केंद्र में तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया लेकिन पहली बार भारतीय संघ के लगभग 9 घटक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी यही वह समय था जब कांग्रेस की शक्ति में क्षीणता आना प्रारंभ हो रही थी ।जब कांग्रेस सत्ता में रहती थी तब विपक्षी दलों को लगता था कि उनका बिखराव ही उन्हें सत्ता से दूर रख रहा है। अतः जनतापार्टी के नेतृत्व में विपक्षी दल लामबंद होना प्रारम्भ हुए। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ सुनने में जनता पार्टी एक दल प्रतीत होता है लेकिन उसमें पांच दल सम्मिलित थे जिसमें जनसंघ, जनता कांग्रेस, कांग्रेस ओ जैसे दल सम्मिलित थे। जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाई और सरकार समय से पहले ही धराशाई हो गई ।1980 और 84 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ ।किंतु 90 के दशक में अधिकांश चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत प्राप्त होना कठिन होता गया फल स्वरुप देश में राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त होने लगी अतः राजनीति में एक विकल्प के तौर पर गठबंधन की राजनीति का उभार हुआ ।समान विचारधारा वाले दलों ने आपस में गठबंधन का निर्माण कर सत्ता में आना प्रारंभ कर दिया। गठबंधन सरकारें भी अस्थिर सरकारें रही जब तक सही ताल मेल एवं नेतृत्व का आभाव रहा। सबसे पहले गठबंधन की राजनीति की व्यावहारिकता को समझने वाले नेता थे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई। अटल बिहारी वाजपेई ने 24 दलों को साथ लेकर चुनाव पूर्व गठबंधन किया ।1999 के चुनाव में जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में आया एवं यह पहली ऐसी गठबंधन सरकार बनी जिसने अपना कार्यकाल पूर्ण किया ।इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए)का निर्माण किया एवं यूपीए गठबंधन को 2014 के लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई इसी प्रकार की सफलता अप यूपीए -2 को भी मिली। 2009 के चुनाव में पिछली बार की तुलना में यूपीए -2 को पहले से ज्यादा सीटें प्राप्त हुईं। 2014 के लोकसभा चुनाव में 1984 के बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक दल को अपने दम पर बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार का गठन भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के घटक दलों को साथ लेकर किया गया ।2019 के चुनाव में भाजपा को 2014 से अधिक सीट प्राप्त हुईं। पिछली बार की तरह ही सरकार का निर्माण एनडीए के घटक दलों को

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

साथ लेकर किया गया अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न हो तो देश की जनता पर पुनः चुनाव थोपा जाता है फलतः गठबंधन की राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करने में सहायक रही है।

गठबंधन-

गठबंधन बहुदलीय सरकार की एक घटना है जहां कई दल सरकार चलाने के उद्देश्य से साथ आते हैं। एक गठबंधन तब बनता है जब कई समूह सामान्य शर्तों पर एक साथ आते हैं और एक सामान्य कार्यक्रम या एजेंडे को परिभाषित करते हैं जिस पर वे काम करते हैं ।भारत जैसे देश में गठबंधन सरकार हमेशा की खींचतान एवं दबाव में रहती है ,हालांकि पिछले दो आम चुनाव से राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर इस प्रवृत्ति में परिवर्तन देखा गया है ।गठबंधन की राजनीति के सिद्धांत को दो सेट में विभाजित कर सकते हैं

जिसमें पहले सेट में दो सिद्धांत हैं

शक्ति अधिकतम करण का सिद्धांत

नीति आधारित सिद्धांत

यह गठबंधन प्रयोगों से संबंधित हैं और उनकी प्रकृति का पता लगाते हैं।

दूसरे सेट में निम्न दो सिद्धांत आते हैं

1.चुनाव प्रणाली सिद्धांत

2.सामाजिक दरार सिद्धांत

सिद्धांत का दूसरा सेट पार्टी प्रणाली के सिद्धांत से संबंधित है ।

भारत में गठबंधन की राजनीति को समझने के लिए चुनाव प्रणाली और सामाजिक सिद्धांत का समावेश महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सीमित पश्चिमी सिद्धांत भारतीय गठबंधन की जटिलता, गतिशीलता, बहुलवाद की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए अपर्याप्त हैं ।

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

2.उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य में मूलतः भारत में गठबंधन की राजनीति की प्रासंगिकता को समझना है ।इसके साथ ही इसके कुछ उद्देश्य इस प्रकार निम्नलिखित हैं

1. भारत में गठबंधन की राजनीति की प्रासंगिकता को समझना ।
2. भारत में गठबंधन की राजनीति के उत्तरदाई कारणों को समझना।
3. गठबंधन सरकारों का विश्लेषण एवं उनकी सफलता एवं असफलता के करणों का विश्लेषण ।
4. अभी तक घटित हुई विभिन्न गठबंधन सरकारों का अध्ययन एवं उनकी कार्य प्रणाली को समझना।

3. शोध प्रविधि-

प्रस्तुत शोध पत्र के लिए वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। शोध सामग्री के लिए द्वितीय शोध आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए विभिन्न पुस्तकों ,लेखों , अखबारों एवं वेबसाइटों का सहारा लिया गया है ।

भारत में गठबंधन की राजनीति की सफलताएं एवं असफलताएं-

अंग्रेजों के आगमन ने आधुनिक भारत के अभूतपूर्व राजनीतिक एकीकरण का नेतृत्व किया। इसने आधुनिक भारत में विविधता में एकता की अवधारणा की शुरुआत की ।भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति और सरकार पर कांग्रेस का वर्चस्व स्थापित किया। भारत एक बहुजातीय, बहुभाषी और बहु सांस्कृतिक समाज रहा है।

औपनिवेशिक मिसालों ने भारत को एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली या कांग्रेस प्रणाली बना दिया । स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने लोगों के बीच लोकप्रियता एवं सम्मान हासिल किया। इस पार्टी का निसंदेह भारत में एक जन आधार और जमीनी आधार था। इसने 1952, 1957 और 1962 में लोकसभा चुनाव के लिए लगातार शासन किया लेकिन धीरे-धीरे जाति ,धर्म ,भाषा आदि जैसी विभिन्न अंशों की जरूरत और आकांक्षाओं ने भारत की विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी के विकल्पों में शरण लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या और खंडित चुनाव परिणामों ने गठबंधन सरकार को

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

अपरिहार्य बना दिया ।एक प्रणाली और पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी का कमजोर होना विभिन्न समुदाय एवं क्षेत्र के लोगों की जरूरत और आकांक्षाओं को पूरा करना और स्वतंत्रता के समय दिखाए गए सपने को साकार करने में इसकी असफलता ने लोगों को न केवल कांग्रेस के विकल्प तलाश करने के लिए मजबूर किया बल्कि सबसे बड़ी सेवा प्रदान करने के लिए पार्टी बनाने के लिए भी प्रेरित किया इससे राज्य स्तर पर राजनीतिक दलों का उदय हुआ ।

इंदिरा गांधी के शासनकाल में उनके कुछ ऐसे व्यक्तिगत निर्णय थे जो अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति के थे। आपातकाल का निर्णय उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण था जो भारत की लोकतांत्रिक इतिहास पर एक धब्बा था ।उस समय एक नारा प्रचलित हो गया था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा । सरकार ने विपक्षी नेताओं ,राजनीतिक- सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया। यही कारण है कि 1977 में सभी विपक्षी दल इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक साथ आए उन्होंने न केवल कांग्रेस को पराजित किया बल्कि भारत में केंद्र में पहली बार पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। यह वह दौर था जब क्षेत्रीय दल मजबूती से उभर रहे थे ।उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों का उदय हुआ जिससे पिछड़े और निम्न तबकों का व्यवस्था में प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा ।कई राजनीतिक विदों ने भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती हुई भूमिका को लोकतंत्र के लिए मजबूती के रूप में देखा। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि गठबंधन की सरकार निर्णय लेने में दुर्बल पड़ जाती है एक राजनीतिक दल के बहुमत को मजबूत सरकार के रूप में देखा जाता है किंतु जब हम भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक का ऐतिहासिक विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं पूर्ण बहुमत वाली सरकार की निरंकुश होने की संभावना ज्यादा रहती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोर होने की संभावना अधिक होती है तो वहीं दूसरी और दुर्बल सरकार ने राजनीतिक अस्थिरता को उत्पन्न करती है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दुर्बल सरकारों ने भी कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है ।विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना ,पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की नीतियों को लागू करना इसके प्रमुख उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं। 1990 का दशक राजनीतिक अस्थिरता के दशक के रूप में माना जा सकता है ।1999 में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में सत्ता में आई तो वही 2004 में कांग्रेस अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ यूपीए के रूप में सत्ता में आई और यह वह दौर था जब

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कुछ ऐसी पारदर्शी नीतियां बनी जिसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य किया मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को मान्यता देना, मनरेगा ,किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति एवं सूचना का अधिकार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सन 2009 से 2014 के मध्य यूपीए के दूसरे शासनकाल में कई घोटाले उजागर हुए। जिसकी वजह से कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और 2014 में भाजपा नरेंद्र मोदी की अगुआई में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई हालांकि भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ अभी भी सत्ता में कायम है।

आगे की राह –

2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने बलबूते पर बहुमत प्राप्त हुआ तब राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा की जाने लगी कि क्या देश की जनता ने अब गठबंधन की राजनीति को नकार दिया है ?इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला लोकतांत्रिक देश है जहां विभिन्न दल सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ते हैं इसके अतिरिक्त यहां क्षेत्रीय ,भाषा गत, जातिय एवं धार्मिक विविधताओं के कारण सभी समुदाय अपने-अपने हितों को अभिव्यक्त करने के लिए राजनीतिक रूप से लामबंद होते रहे हैं।भाजपा 2014 से 2019 तक इसके बाद 2019 से 2024 तक भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त था तब गठबंधन की राजनीति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगा था वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से दूर रही एवं देश को पुनः गठबंधन सरकार की प्राप्ति हुई जो एनडीए पिछले एक दशक से सत्ता में है वहीं एनडीए सरकार अब गठबंधन की वजह से अब सत्ता में है इसलिए भविष्य में गठबंधन की राजनीति से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।

4.निष्कर्ष-

भारत एक बहुभाषी, बहू धर्मो विविधता वाला देश है यहां विभिन्न समुदायों के हित अलग-अलग हैं।ये समुदाय अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं तथा इसकी परिणीति क्षेत्रीय दलों के उदय में देखी जा सकती है।राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की शक्ति में निरंतर हास एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। फल स्वरुप किसी एक दल को बहुमत मिलना कठिन हो गया है भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति ने शुरुआत से ही एक विकल्प प्रस्तुत किया

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

है जिसकी परिणति विभिन्न गठबंधन सरकारों के निर्माण में देखी जा सकती है। वर्ष 2014 में जब भाजपा को अकेले बहुमत प्राप्त हो गया तब कहा जाने लगा कि अब गठबंधन की राजनीति का दौर समाप्त हो गया है ऐसा ही 2019 के चुनाव में भी हुआ लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह सिलसिला थम गया भाजपा बहुमत से दूर रह गई और उसे सरकार में आने के लिए अपने सहयोगियों का सहारा लेना पड़ा।

5.संदर्भ-ग्रंथ-

1. बी. एल. फाड़िया, भारतीय शासन एवं राजनीति, 2014

2. विद्युत चक्रवर्ती, कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, 2014

3. एस. आर. महेश्वरी,स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, 2001

4.सुभाष सी कश्यप, कोलेशन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया

5. https://eci.gov.in